

### III. बाह्य क्षेत्र

मुख्यतः बढ़ते बाजार घाटे की वजह से तीसरी तिमाही में सीएडी-जीडीपी अनुपात अब तक के सर्वोच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंचने के कारण 2012-13 के दौरान बाह्य असंतुलन उभर कर सामने आए। यद्यपि हाल के महीनों में गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयातों में गिरावट आई है फिर भी स्टिकी तेल और स्वर्ण आयातों के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा और भी बढ़ा। तथापि एफआईआई निवेशों के नेतृत्व में मजबूत पूंजी अंतर्प्रवाहों के कारण कुल भुगतान संतुलन की स्थिति थोड़ी सरप्लस में रही। 2012-13 की चौथी तिमाही में निर्यात वृद्धि की पुनर्बहाली तथा आयात वृद्धि के स्थिरीकरण के फलस्वरूप सीएडी के कम होने की आशा है। जिस मूल्यों में हाल की कमी, जिसमें तेल और सोना भी शामिल हैं, भी चालू खाते पर दबाव को घटाएगी। इन कारकों के बावजूद सीएडी के, धारणीय स्तर से ऊपर ही बने रहने की संभावना है। इसके लिए नीतिगत ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि पूंजीगत प्रवाहों की अपवृद्धि और चंचलता सीएडी वित्तीयन को, इन प्रवाहों के अचानक बंद होने अथवा उलट जाने के खतरों से रूबरू करवाती है।

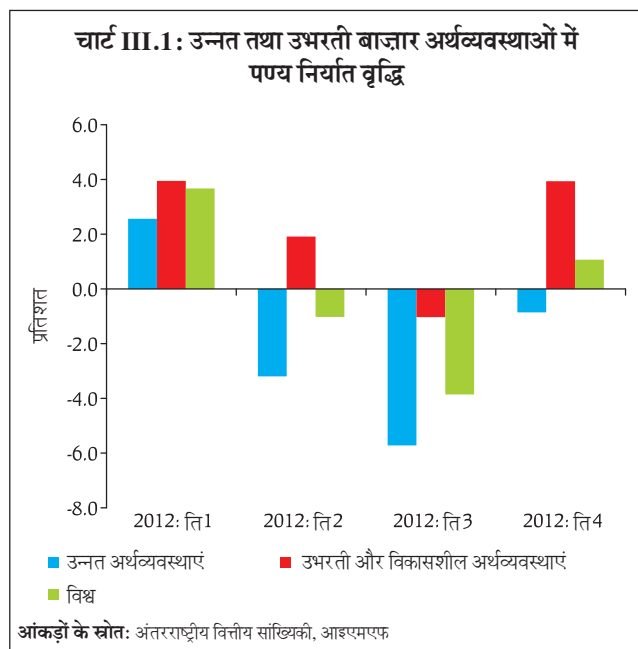
#### वैश्विक पुनरुज्जीवन के कोई निश्चित संकेत नहीं

III.1 2012 के दौरान विश्व व्यापार 1990 के दशक के मध्य से अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ा जिसमें 2009 में एक बड़ा कांटेक्शन अपवाद था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि वैश्विक व्यापार विस्तार में एक कमजोर कड़ी बनी रही जबकि

उभरता बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई), वृद्धित इन्ट्रा-उद्योग तथा दक्षिण-दक्षिण व्यापार के माध्यम से वैश्विक व्यापार में योगदान करती हुई प्रतीत हुई। चाहे छोटा ही सही, 2012 की चौथी तिमाही में विश्व निर्यातों में उठान ईएमडीई के अपेक्षाकृत बेहतर वृद्धि कार्यानिष्पादन द्वारा ही अधिकांशतः समर्थित रहा जबकि उन्नत “अर्थव्यवस्थाओं से निर्यातों” ने संकुचन दिखाया (चार्ट III.1)। इसके अतिरिक्त 2013 की पहली तिमाही में चीन में हुई प्रत्याशा से कम वृद्धि, एक और निराशा लाई है और इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा व्यापार आउटलुक के लिए जोखिमों के कुल संतुलन को नीचे की ओर झुका दिया।

#### 2012-13 की चौथी तिमाही में निर्यात बढ़े

III.2 ईएमडीई में व्यापारिक गतिविधियों में संतुलित वृद्धि परिलक्षित करते हुए पिछले महीनों के कमजोर कार्यानिष्पादन के बाद दिसंबर 2012 से भारत के पण्य निर्यातों में एक टर्न अराउंड दिखा (तालिका III.1) तथा (चार्ट III.2ए)। 2011-12 की तदनुरूपी अवधि के 4.0 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 की चौथी तिमाही में 4.7 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि अधिक थी। जहां जनवरी 2013 में, निर्यातों में रिकवरी अधिकांशतः सऊदी अरब, मलेशिया तथा कुछ अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं से उच्च मांग की वजह से संभव हुई वहीं चीन को किये गये निर्यातों में सिकुड़न जारी रही। पण्यवार आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्यात का

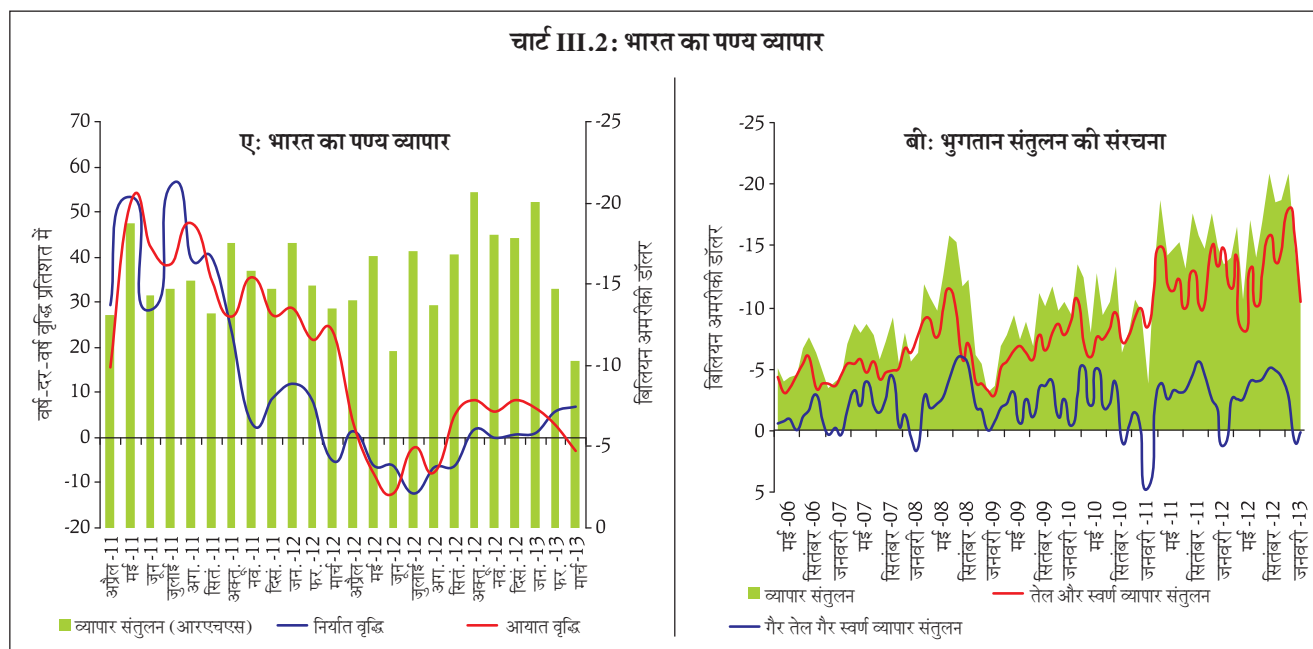


तालिका III.1: भारत का पण्य व्यापार

(अमरीकी डॉलर \$ बिलियन)

वर्ग	अप्रैल-मार्च			
	2011-12 आर		2012-13 पी	
	वैल्यू	वृद्धि (%)	वैल्यू	वृद्धि (%)
1	2	3	4	5
निर्यात	306.0	21.8	300.6	-1.8
जिसमें से :				
तेल	56.0	35.1	60.0	7.1
गैर-तेल	249.9	19.2	240.6	-3.7
स्वर्ण	6.7	10.8	6.5	-3.5
गैर तेल गैर-स्वर्ण	243.2	19.5	234.1	-3.8
आयात	489.3	32.3	491.5	0.4
जिसमें से :				
तेल	155.0	46.2	169.3	9.2
गैर-तेल	334.4	26.7	322.2	-3.6
स्वर्ण	56.5	38.9	54.0 @	-4.4
गैर तेल गैर-स्वर्ण	277.9	24.5	268.3 @	-3.5
व्यापार घाटा	-183.4		-190.9	
जिसमें से :				
तेल	-98.9		-109.3	
गैर-तेल	-84.4		-81.7	
गैर तेल गैर-स्वर्ण	-34.7		-34.2	

@ : रिजर्व बैंक अनुमानों पर आधारित आर: संशोधित पी: अनंतिम



यह उठान, केवल कुछ सेक्टरों तक ही सीमित था। पेट्रोलियम उत्पादों, तेल की खली, रत्न और आभूषण, इन्जीनियरिंग वस्तुएं तथा कॉटन यार्न ने 2012-13 की चौथी तिमाही में निर्यातों में हुई कुल वृद्धि का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्राप्त किया।

III.3 हाल के महीनों में निर्यातों में हुई अच्छी वृद्धि के बावजूद 2012-13 में निर्यात घाटा काफ़ी अधिक बना रहा। वस्तुतः गैर तेल, गैर-स्वर्ण व्यापार संतुलन में नवंबर 2012 से सुधार दिखा है और फरवरी 2013 में यह थोड़ा सकारात्मक भी बन गया है (चार्ट III.2बी) पीओएल तथा स्वर्ण का निवल आयात 2012-13 के दौरान भारत के व्यापार घाटे का लगभग 82 प्रतिशत था।

III.4 हाल की अवधि में सरकार ने ऊँचे व्यापार घाटे, जिसका कारण कम निर्यातों तथा उच्च पीओएल और स्वर्ण आयातों को बताया जाता है, का समाधान करने के लिए कुछ उपाय किए। जनवरी 2013 में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को मासिक आधार पर डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए प्राधिकृत कर दिया और इस प्रकार डीजल की कीमतों के शनैः शनैः अ-विनियमन को अनुमति प्रदान कर दी।

III.5 सोने की आयात मांग पर अंकुश लगाने के लिए स्वर्ण आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर जनवरी 2013 में इसे 4 से 6 प्रतिशत कर दिया गया। स्वर्ण जमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपने सोने का कुछ हिस्सा बैंकों के पास जमा करवाने की अनुमति म्युच्युअल फंडों / ईटीएफ को दी है। उच्च स्वर्ण आयातों तथा भारत के चालू खाते घाटे पर इसके असर से जुड़ी

चिंताओं को देखते हुए 2013-14 के केंद्रीय बजट में इस बात पर बल दिया गया है कि परिवार क्षेत्र को सोना खरीदने के बजाय वित्तीय लिखतों में बचत करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए और इस प्रकार मुद्रास्फीति - सूचकांकित बांडों की शुरुआत सहित कई उपाय प्रस्तावित किए।

**सीएडी जोखिम निकट भविष्य में धीमे हो सकते हैं हालांकि संरचनात्मक रुकावटें बनी रहेंगी**

III.6 2012-13 की तीसरी तिमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के 67 प्रतिशत के उच्च ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया (तालिका III.2)। भुगतान संतुलन आधार पर पण्य निर्यात 2011-12 की तीसरी तिमाही में प्राप्त स्तर पर ही प्रायः बने रहे। हालांकि निरंतर कमजोर निर्यातों के लिए धीमी वैश्विक मांग ही अधिकांशतः उत्तरदायी रही है फिर भी निर्यात वृद्धि में रुकावट डालने वाले घरेलू नीतिगत मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उदाहरणतः विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादकों में से एक होने के बावजूद भारत को अप्रैल 2012-जनवरी 2013 के दौरान 113 मिलियन टन का आयात करना पड़ा, जो कि पिछले वर्ष के दौरान देखे गए 47 प्रतिशत के उठान के ऊपर 29 प्रतिशत की छलांग है। 2012-13 में डीजल की खपत 2011-12 के मुकाबले 6.8 प्रतिशत बढ़ी।

III.7 चालू प्राप्तियों के अन्य प्रमुख स्रोत, अर्थात् सेवाओं के निर्यात, अधिकांशतः सॉफ्टवेयर तथा निजी अंतरणों में, भी गिरावट आई और इस प्रकार वे चालू खाता शेष में उच्च व्यापार घाटे के असर को उलटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। गैर-तेल, गैर-

तालिका III.2: भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य मदें

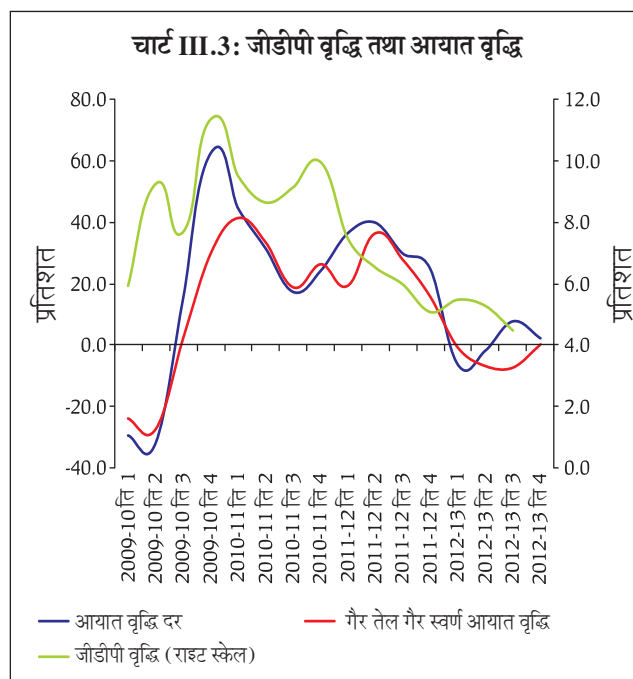
(बिलियन अमरीकी डॉलर)

1	2011-12 (पीआर)	2011-12				2012-13		
		ति1 (पीआर)	ति2 (पीआर)	ति3 (पीआर)	ति4 (पीआर)	ति1 (पीआर)	ति2 (पीआर)	ति3 (पी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वस्तु निर्यात	309.8	78.8	79.6	71.5	80.0	76.7	69.8	71.8
2. वस्तु आयात	499.5	123.7	124.1	120.1	131.7	119.1	118.1	131.4
3. व्यापार संतुलन (1-2)	-189.7	-44.9	-44.5	-48.6	-51.7	-42.4	-48.3	-59.6
4. सेवाएं निर्यात	140.9	33.7	32.3	37.3	37.7	34.8	34.6	36.5
5. सेवाएं आयात	76.9	17.4	18.3	21.1	20.0	20.7	19.4	18.9
6. निवल सेवाएं (4-5)	64.0	16.3	14.0	16.1	17.7	14.1	15.2	17.6
7. वस्तु और सेवा संतुलन (3+6)	-125.7	-28.6	-30.5	-32.5	-34.0	-28.3	-33.1	-42.0
8. प्राथमिक आय (निवल)	-16.0	-3.6	-4.0	-3.8	-4.6	-4.9	-5.6	-6.3
9. द्वितीयक आय (निवल)	63.5	14.8	15.6	16.2	16.9	16.8	16.1	15.7
10. निवल आय (8+9)	47.5	11.2	11.6	12.4	12.3	11.9	10.5	9.4
11. चालू खाता बैलेन्स (7+10)	-78.2	-17.4	-18.9	-20.2	-21.7	-16.4	-22.6	-32.6
12. पूंजी खाता बैलेन्स	-0.1	-0.3	0.2	0.1	-0.2	-0.3	-0.2	0.01
13. वित्तीय खाता बैलेन्स	80.7	18.7	19.0	20.6	22.4	15.8	23.9	31.1
जिसमें से : रिजर्व्स में परिवर्तन*	12.8	-5.4	-0.3	12.8	5.7	-0.5	0.2	-0.8
14. नुटियां और ऑमीशंज (11+12-13)	-2.4	-0.9	-0.4	-0.5	-0.6	0.9	-1.0	1.6
मेमो : जीडीपी से अनुपात के रूप में								
15. व्यापार बैलेन्स	-10.1	-9.7	-9.8	-10.6	-10.5	-9.9	-11.5	-12.3
16. निवल सेवाएं	3.3	3.6	3.1	3.5	3.5	3.3	3.6	3.6
17. निवल आय	2.5	2.4	2.6	2.7	2.5	2.8	2.5	1.9
18. चालू खाता बैलेन्स	-4.2	-3.8	-4.2	-4.3	-4.4	-3.9	-5.4	-6.7
19. पूंजी और वित्तीय एकाउंट निवल (रिजर्व्स में परिवर्तनों को छोड़कर)	3.6	5.2	4.3	1.7	3.3	3.7	5.6	6.5

टिप्पणी : \* : -/+ यह चिह्न रिजर्व्स में क्रमशः वृद्धि/गिरावट बताता है।  
उप घटक का जोड़, राउंडिंग ऑफ के कारण, एग्ग्रेगट के साथ मिलान नहीं खा सकता है  
पी : प्रारंभिक; पीआर: आंशिक रूप से संशोधित

स्वर्ण आयातों में भी निरंतर गिरावट रही और वे भी मुख्यतः जीडीपी वृद्धि में धीमेपन को ही ट्रैक करते रहे (चार्ट-III.3)। इसकी तुलना में वृद्धि में धीमेपन, रुपए के मूल्यहास तथा स्वर्ण पर शुल्क में बढ़ोतरी जैसे नीतिगत उपायों आदि विभिन्न धीमी गति लाने वाले कारकों के बावजूद तेल और सोने के आयातों की मांग काफी बनी हुई है।

III.8 वैश्विक जिंस कीमतों, खास तौर पर तेल और सोने की कीमतों, में हाल ही में गिरावट आई है। तेल की कीमतों में नरमाई मुख्यतः कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा साथ ही चीन की धीमी वृद्धि की संभावनाओं को परिलक्षित करती है। अमरीकी डॉलर के मजबूत होने से एक सुरक्षित आस्ति के रूप में सोने की भूमिका भी कमजोर हो गई। इसके अलावा कुछ कर्जदार यूरो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं द्वारा स्वर्ण की बिक्री की संभावना भी सोने की कीमतों में गिरावट का कारण बन गई प्रतीत होती है। तेल और सोने की कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप अल्पावधि में



चालू खाते घाटे दर दबाव थोड़ा कम चाहे हो गया हो मगर इसमें ढिलाई बरतने की कोई संभावना नहीं है।

III.9 चाहे इस बड़े स्तर पर भी चालू खाते घाटे का पूर्ण वित्त पोषण 2012-13 के दौरान किया जाना संभव हो मगर इन प्रवाहों में उतार-चढ़ाव एक जोखिम ही रहता है। धीमी वृद्धि तथा साथ ही इससे जुड़े वृहद् वित्तीय जोखिमों और वैश्विक 'रिस्क ऑफ' के वैश्विक 'रिस्क ऑन' बनने की संभावनाओं को देखते हुए, जिससे कि उभरते बाजारों से पूंजी प्रवाहों का रिवर्सल हो सकता है, यह जरूरी है कि सीएडी को इसके धारणीय स्तर पर नीचे लाकर बाह्य क्षेत्र जोखिमों को कम किया जाए न कि बाहरी अंतःप्रवाहों के बारे में ढिलाई बरती जाए। कुल मिलाकर निजी क्षेत्र बाह्य कर्ज काफी बढ़ा हो गया है, और बाहरी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) तथा अल्पावधि व्यापार क्रेडिट के संबंध में आगे कुछ विवेक आवश्यक होगा।

**पूंजी प्रवाह मजबूत बने हुए हैं जिससे सीएडी का वित्त पोषण संभव हो सकता है**

III.10 यद्यपि 2012-13 की तीसरी तिमाही में सीए घाटा तेजी से बढ़ा तथापि निवल पूंजी प्रवाह इसे पूर्णतः वित्त पोषित करने में समर्थ थे और यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा भंडारों में थोड़ी सी बढ़ोतरी भी हुई। यद्यपि पोर्टफोलियो प्रवाहों ने व्यापक रूप से 2012-13 की चौथी तिमाही में वैश्विक आशावाद का ही पीछा किया, वहीं घरेलू नीतिगत उपायों ने एफआईआई प्रवाहों को आकर्षित करने के लिए 'पुल-फैक्टर्स' का काम किया। तीसरी तिमाही में कर्ज प्रतिभूतियों, कारपोरेट तथा सरकारी, दोनों में एफआईआईसीमाओं को बढ़ाने के अतिरिक्त चौथी तिमाही में विभिन्न नीतिगत घोषणाओं ने भी बाजार के रुख में सुधार किया। इन घोषणाओं में शामिल थीं : (i) जनरल एंटी-अवायडेंस नियम (जीएएआर) के कार्यान्वयन को दो वर्षों के लिए स्थगित करना (ii) विदेशी निवेशकों के लिए "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी पंजीकरण नियमों का सरलीकरण तथा (iii) विभिन्न

### सारणी III.3: वित्तीय खाते की भिन्न-भिन्न मदें

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

	2011-12 (पीआर)	2011-12				2012-13		
		ति1 (पीआर)	ति2 (पीआर)	ति3 (पीआर)	ति4 (पीआर)	ति1 (पीआर)	ति2 (पीआर)	ति3 (पी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. प्रत्यक्ष निवेश (निवल)</b>	<b>22.1</b>	<b>9.3</b>	<b>6.5</b>	<b>5.0</b>	<b>1.4</b>	<b>3.9</b>	<b>8.9</b>	<b>2.5</b>
1.ए भारत में सीधा निवेश	33.0	12.4	9.5	6.9	4.2	5.9	10.3	4.8
1.बी भारत द्वारा सीधा निवेश	-10.9	-3.1	-3.0	-1.9	-2.9	-2.1	-1.4	-2.3
<b>2. पोर्टफोलियो निवेश</b>	<b>16.6</b>	<b>2.3</b>	<b>-1.4</b>	<b>1.8</b>	<b>13.9</b>	<b>-2.0</b>	<b>7.6</b>	<b>8.6</b>
2.ए भारत में सीधा निवेश	16.8	2.5	-1.6	1.9	14.1	-1.7	7.9	9.8
2.बी भारत द्वारा सीधा निवेश	-0.2	-0.2	0.2	-0.04	-0.2	-0.3	-0.3	-1.2
3. वित्तीय व्युत्पन्न तथा कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-	-0.6	-0.5	-0.4
<b>4. अन्य निवेश</b>	<b>29.2</b>	<b>12.6</b>	<b>14.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1.4</b>	<b>15.1</b>	<b>7.7</b>	<b>21.0</b>
4.ए अन्य इक्विटी (एडीआर्ज/जीडीआर्ज)	0.6	0.3	0.2	0.1	0.03	0.1	0.1	0.2
4.बी मुद्रा तथा डिपॉजिट	12.1	1.2	3.1	3.2	4.6	6.4	3.5	2.6
सेंट्रल बैंक को छोड़कर डिपॉजिट लेनेवाली निगमों (एनआरआई डिपॉजिटर्स)	11.9	1.2	2.8	3.3	4.7	6.6	2.8	2.7
4.सी ऋण*	16.8	14.9	9.5	-7.7	-0.03	3.8	3.2	7.1
4.सी.ि भारत को ऋण	15.7	14.9	8.9	-8.1	-0.02	3.7	3.5	7.2
सेंट्रल बैंक को छोड़कर डिपॉजिट लेने वाली निगमों	4.1	11.5	3.9	-8.7	-2.6	3.0	2.0	2.7
जनरल सरकार (विदेशी/बाह्य सहायता)	2.5	0.4	0.3	1.4	0.3	0.3	0.2	1.5
अन्य क्षेत्र (ईसीबीज)	9.1	3.0	4.7	-0.8	2.3	0.4	1.2	3.1
4.सी.ि.ि भारत द्वारा ऋण	1.0	-0.02	0.6	0.5	-0.01	0.1	-0.3	-0.1
जनरल सरकार (बाह्य सहायता)	-0.2	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.1	-0.1	-0.1
अन्य सेक्टर (ईसीबीज)	1.2	0.02	0.6	0.5	0.03	0.1	-0.3	-0.1
4.डी व्यापार क्रेडिट तथा अग्रिम	6.7	3.1	2.9	0.6	0.2	5.4	4.1	6.2
4.ई अन्य खाते प्राय/देय-अन्य	-6.9	-6.8	-1.5	4.8	-3.3	-0.6	-3.2	5.0
<b>5. रिजर्व आस्तियां</b>	<b>12.8</b>	<b>-5.4</b>	<b>-0.3</b>	<b>12.8</b>	<b>5.7</b>	<b>-0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>-0.8</b>
<b>वित्तीय एकाउन्ट (1+2+3+4)</b>	<b>80.7</b>	<b>18.7</b>	<b>19.0</b>	<b>20.6</b>	<b>22.4</b>	<b>15.8</b>	<b>23.9</b>	<b>31.1</b>

टिप्पणी : उप घटकों का जोड़ राउंडिंग ऑफ के कारण एग्रीगेट के साथ मिलान नहीं खा सकता है।

पी: प्रारंभिक; पीआर: आंशिक रूप से संशोधित

\*: इसमें बाह्य सहायता, ईसीबीज, गैर-एनआरआई बैंकिंग पूंजी तथा अल्पावधि व्यापार क्रेडिट शामिल हैं।

**तालिका III.4: पूंजी प्रवाह**

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

घटक	2011-12				2012-13			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
	मासिक प्रवाहों का औसत							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत में एफडीआई	4.1	3.1	2.3	1.5	2.0	3.4	1.8	2.9*
भारत द्वारा एफडीआई	1.0	1.0	0.6	1.0	0.7	0.5	0.8	0.1
विदेशी संस्थागत निवेशक	0.8	-0.5	0.6	4.7	-0.6	2.6	3.3	3.8
ईसीबी	1.0	1.6	-0.3	0.8	0.1	0.4	1.0	1.3
एनआरआई	0.4	0.9	1.1	1.6	2.2	0.9	0.9	0.7*

\*: जनवरी-फरवरी 2013.

प्रकार के कार्पोरेट बाँडों पर विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अलग से सीमाएं हटाना। हाल ही में वैश्विक जिंस कीमतों में आई गिरावट ने, सीएडी जोखिमों को कुछ हद तक बढ़ा दिया है और इस प्रकार एफआईआई अंतर्प्रवाहों को और अधिक आकर्षित किया है तथापि इसका वित्त-पोषण एक चुनौती बना हुआ है।

III.11 जहां चौथी तिमाही में गैर कर्ज प्रवाहों ने जोर पकड़ा वहीं कर्ज निर्माण प्रवाहों के प्रमुख घटकों में एक मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। जहाँ चौथी तिमाही में अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों में धीमापन आया वहीं ईसीबी के रूप में नैट प्रवाहों में वृद्धि दिखाई दी (तालिका III.4)। एनआरआई जमाराशियों में धीमापन, अंशतः प्रमुख स्रोत देशों में धीमी आय वृद्धि स्थितियों को परिलक्षित करता है। चौथी तिमाही के दौरान ईसीबीज को, प्रमुखतः, बिजली क्षेत्र आधुनिकीकरण, पूंजी वस्तुओं के आयात, तथा नई परियोजनाओं के निधीयन के लिए ही जुटाया गया है। बढ़ते निजी बाह्य कर्ज को देखते हुए यह जरूरी है कि ईसीबी के अंतिम उपयोग पर नजर रखी जाए।

### पोर्टफोलियो प्रवाहों द्वारा समर्थित रुपया रेंजबद्ध रहा

III.12 दिसंबर 2012 से 2013 की फरवरी की शुरुआत के दौरान देखी गई रुपए की मजबूत प्रवृत्ति, पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाहों तथा अवधि के दौरान घोषित विभिन्न सुधार उपायों द्वारा समर्थित थी। हालांकि फरवरी के दूसरे सप्ताह से मार्च के शुरु के दौरान रुपए में कुछ कमजोरी दिखाई परंतु बाद में अप्रैल 2013 के दौरान कुछ थोड़े उठान के साथ यह अधिकांशतः सीमाबद्ध ही रहा। चौथी तिमाही में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (6 तथा 36 मुद्रा बास्केटों पर आधारित आरईईआर) का स्तर तीसरी तिमाही में दर्ज स्तर (औसत आधार) जितना ही प्रायः रहा। 2012-13 में आरईईआर ने कुछ मूल्यहास देखा (तालिका III.5)।

**तालिका III.5: नोमिनल तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दरें : व्यापार आधारित (आधार: 2004-05=100)**

	सूचकांक मार्च 28, 2013 (पी)	वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन (औसत) 2011-12	वि.व. बदलाव (मार्च 2012 समक्ष 28 मार्च 2013)
1	2	3	4
36-आरईईआर	95.8	-6.7	-2.7
36-एनईईआर	79.1	-10.4	-5.9
6-आरईईआर	106.9	-5.9	-2.4
6-एनईईआर	76.8	-10.3	-5.9
रुपए/अमरीकी डॉलर	54.4	-11.9	-7.5

एनईईआर: नोमिनल प्रभावी विनिमय दर

आरईईआर: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर पी : अस्थायी/अनतिम

टिप्पणी : सूचकांकों में वृद्धि रुपये में वृद्धि और विलोमत : दर्शाती है।

### बाह्य कर्ज विशेषकर अल्पावधि कर्ज तीसरी तिमाही में और बढ़ा

III.13 दिसंबर 2012 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 376 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो बढ़ते चालू खाते घाटे को पूरा करने के लिए ईसीबी तथा अल्पावधि उधारों पर निरंतर निर्भरता को परिलक्षित करता है (तालिका III.6)। 2012-13 की पहली तीन तिमाहियों में अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अल्पावधि कर्ज लगभग 19 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ा है।

**तालिका III.6: भारत का विदेशी कर्ज**

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

संकेतक	मार्च अंत 2012 (पीआर)	जून अंत 2012 (पीआर)	सितं. अंत 2012 (क्यूई)	दिसं. अंत 2012 (क्यूई)	प्रतिशत बदलाव (सितं. अंत 2012 के मुकाबले दिसं. अंत 2012)
1	2	3	4	5	6
1. मल्टीलेटरल	50.5	49.7	50.7	51.6	1.8
2. द्विपक्षीय	26.9	27.4	27.9	26.3	-5.4
3. आइएमएफ	6.2	6.0	6.1	6.1	-0.3
4. ट्रेड क्रेडिट (1 वर्ष से ऊपर)	19.0	19.1	19.1	18.5	-2.8
5. ईसीबीज	104.8	104.3	108.8	113.0	3.8
6. एनआरआई जमाराशियां	58.6	60.9	67.0	67.6	0.9
7. रुपया कर्ज	1.4	1.2	1.3	1.3	-3.7
8. दीर्घावधि (1 से 7)	267.3	268.6	280.9	284.4	1.3
9. अल्पावधि (मूल परिपक्वता)	78.2	80.5	84.7	91.9	8.5
10. अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता) #	147.4	150.0	159.6	166.1	4.1
<b>जोड़ (8+9)</b>	<b>345.5</b>	<b>349.1</b>	<b>365.6</b>	<b>376.3</b>	<b>2.9</b>

पीआर : आंशिकतः संशोधित, क्यूई: त्वरित अनुमान, #: रिजर्व बैंक अनुमान

टिप्पणी : वृद्धि दरें 3 दशमलव बिंदुओं तक के डाटा पर आधारित हैं।

**भेद्यता (वलनरेबिलिटी) संकेतक और कमजोर हुए**

III.14 भारत के बाह्य क्षेत्र असुरक्षितता संकेतक 2012-13 की तीसरी तिमाही में और आगे कमजोर हुए (तालिका III.7)। नॉमिनल जीडीपी (रूप के अर्थों में) में वृद्धि की तुलना में विदेशी कर्ज में तेज वृद्धि को परिलक्षित करते हुए तीसरी तिमाही में जीडीपी से बाह्य कर्ज अनुपात बढ़ा। इसी प्रकार चूँकि अवधि के दौरान आयात अधिकांशतः तेल तथा स्वर्ण आयातों के कारण बढ़े, इसलिए आयात कवर थोड़ा-सा गिरा। चौड़े होते चालू खाते घाटे को परिलक्षित करते हुए दिसंबर 2012 के अंत में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश देयता - जीडीपी अनुपात बढ़कर 15.4 प्रतिशत हो गया जबकि 2012 के सितंबर अंत में यह 15.1 प्रतिशत था। चालू खाते घाटे को धारणीय स्तरों पर लाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है यद्यपि जिंस मूल्यों में गिरावट अस्थायी राहत दिला सकती है।

**हालांकि जिंस मूल्यों में गिरावट अस्थायी राहत लाती है मगर सीएडी को धारणीय स्तर पर लाने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है**

III.15 दिसंबर 2012 से निर्यात वृद्धि सकारात्मक हुई और इससे 2012-13 की चौथी तिमाही में सीएडी कम होने के अच्छे संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण और पीओएल

तालिका III.7: बाह्य क्षेत्र भेद्यता संकेतक

संकेतक	(प्रतिशत)		
	मार्च अंत 2012	सितंबर अंत 2012	दिसंबर अंत 2012
1	2	3	4
1. जीडीपी से कुलकर्ज अनुपात*	19.7	19.3	20.6
2. कुल कर्ज से अल्पावधि अनुपात (मूल परिपक्वता)	22.6	23.2	24.4
3. कुल कर्ज से अल्पावधि अनुपात (अवशिष्ट परिपक्वता)#	42.6	43.7	44.1
4. कुल कर्ज से रियायती कर्ज अनुपात	13.9	13.2	12.5
5. कुल कर्ज से प्रारक्षित निधियां अनुपात	85.2	80.7	78.6
6. प्रारक्षित निधियों से अल्पावधि कर्ज अनुपात	26.6	28.7	31.1
7. प्रारक्षित निधियों से अल्पावधि कर्ज अनुपात (अवशिष्ट परिपक्वता)#	50.1	54.1	56.2
8. आयातों के रिजर्व्स कवर (माह में)	7.1	7.2	7.1
9. कर्ज सर्विस अनुपात (चालू प्राप्तियों से कर्ज सर्विस भुगतान)	6.0	6.0	5.8
10. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआइआइपी) (बिलियन अमरीकी डॉलर)	-248.5	-271.5	-282.0
11. एनआइआइपी/जीडीपी अनुपात	-13.3	-15.1	-15.4

\* : चालू बाजार कीमतों पर वार्षिकीकृत जीडीपी

- : उपलब्ध नहीं # : आरबीआइ एस्टीमेट्स

जो भारत के आयातों का लगभग 45 प्रतिशत बनते हैं, की कीमतों में, हाल में आई गिरावट व्यापार घाटे और उसके परिणामस्वरूप सीएडी पर दबाव को कम करने में मदद करेगी। हालांकि सीएडी - जीडीपी अनुपात में 2012-13 की चौथी तिमाही में कमी आने की आशा है मगर फिर भी, अल्पावधि से मध्यावधि में, इसके धारणीय स्तर से अधिक ही बने रहने की आशा है। पूंजी प्रवाह विशेषकर इक्विटी प्रवाह मजबूत बने हुए हैं, जो प्रमुखतः आसान वैश्विक चलनिधि (पुश फैक्टर) तथा भारतीय बाजारों से बाजार सहभागियों की उच्चतर प्रतिफलों की आशाओं (पुल फैक्टर), को परिलक्षित करते हैं। व्यापार घाटे पर घटते दबाव तथा उच्चतर पूंजी प्रवाह मिलकर सीएडी के आसान वित्त पोषण को सुगम बना सकते हैं। इसके बावजूद बहुत से जोखिम अभी भी हैं, जिनके लिए नीतियाँ बनानी जरूरी हैं। पहले, हालांकि पीओएल तथा सोने की कीमतें कम हो रही हैं फिर भी सीएडी में कमी इतनी पर्याप्त नहीं हो पाएगी कि वह धारणीय स्तर तक नीचे आ सके। दूसरे, पीओएल तथा स्वर्ण आयातों के अलावा सीएडी में कमी आने के समक्ष कुछ अन्य रुकावटें भी हैं। भारतीय निर्यातों को उत्पादकता आधारित स्पर्धा निर्मित करने की जरूरत है और इस संदर्भ में इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी रुकावटों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे कारक जो बहिर्जनित स्वरूप के हैं उनसे आराम महसूस करना गलती होगी जैसे कि तेल और सोने की कीमतों में गिरावट। स्थिति में सुधार के लिए पहले घरेलू संरचनागत समस्याओं को सुलझाना होगा। तीसरे, चाहे इस समय एफआइआइ प्रवाह मजबूत बने हुए हैं फिर भी, यदि वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ प्रतिकूल हो गईं, तो ये भी अस्थिर हो सकते हैं। इसके अलावा इन प्रवाहों की निरंतरता भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाओं पर निर्भर है और इन संभावनाओं में थोड़ी भी अनिश्चितता आई तो इन प्रवाहों पर असर पड़ सकता है। चौथे, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं भी खास अच्छी नहीं हैं, और खतरे काफी बने हुए हैं। इसलिए ऐसी अनिश्चित स्थिति में भारतीय निर्यात की बहाली को बनाए रखना एक चुनौती भरा कार्य हो सकता है और इसके लिए उत्पादकता आधारित स्पर्धा बढ़ाने के लिए घरेलू प्रयासों की जरूरत है। सारांश में हालांकि हाल की घटनाओं ने, सीएडी जोखिमों से थोड़ी अस्थायी राहत जरूर दिलवाई और इसके वित्त पोषण पर आए दबाव को घटाया है परंतु इसे धारणीय स्तर पर नीचे लाने के लिए निरंतर नीतिगत प्रयास करने होंगे।